बिहार राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का समग्र विकास

कौशल मणी

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग सामाजिक उत्थान चाहते है और उनमें ऐसी धारणा उत्पन्न हो रही है कि विकास के लाभ उन लोगों तक नहीं पहुँच रही है। जबकि विकास से संबंधित योजनाएँ उन लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। इन लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार के मंत्रालय और विभाग विफल हो रहे है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में ओर अधिक स्वतंत्रता लचीलापन एवं नवीनता की आवश्यकता है। सरकार को चाहिये कि बहुत से गैर–सरकारी संगठनों के मूल्यवान अनुभवों का लाभ उठाये और गैर–सरकारी संगठन भी यही चाहते है कि वे इस कार्य में सरकार के साथ लगातार सहयोग करें। इसलिए सरकार और गैर–सरकारी संगठनों के बीच सहयोगी सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता है। ऐसे सुस्पष्ट पारदर्शी तथा कार्य के प्रति समर्पित होने चाहिए। गैर–सरकारी संगठनों के लिए जो धन की व्यवस्था की जाती है। उस धन राशि को कुशलता और ईमानदारी के साथ बिना किसी संभावित भ्रष्टाचार के साथ खर्च किया जाए।